इंदौर | बुधवार | 2 सितंबर 2026 | वर्ष 66 | अंक 220 | पृष्ठ 20 | मूल्य रु. 6.00
navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत
राष्ट्रीयता का प्रहरी 1934 से

पाक पीएम शहबाज को मोदी की **दो टूक**

आतंक पर किसी भी सूरत में डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा

बश्केक, 1 सितंबर (एजेंसी). किर्गिस्तान के बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सदस्यों देशों के प्रमुखों की मौजूदगी में अपरोक्ष रूप से स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद पर पाकिस्तान का दशकों से चला आ रहा डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलने वाला है.

मोदी ने दो टूक लहजे में कहा कि जो देश आतंकवाद को अपनी नीति के एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक हथियार नहीं बन सकता. समिट में भारत का मुख्य फोकस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा पर है. भारत बाहरी दबावों के बीच प्राथमिकताओं और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए यूरेशिया की बड़ी शक्तियों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है.

पाक ने हटाई मोदी की तस्वीर: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई एक ग्रुप फोटो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, समिट के दौरान ली गई ग्रुप फोटो को एडिट करके प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी गई है. यह तस्वीर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ली गई थी.

एससीओ समिट

समिट में पीएम का मुख्य फोकस

- भारत ऐसे सभी प्रयासों का समर्थन करता है, जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को आसान बनाएं और विकास के नए रास्ते खोलें. हालांकि, यह भी जरूरी है कि ऐसे प्रयास सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें.
- ड्रग तस्करी सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि यह युवा पीढ़ी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. उन्होंने एससीओ के तहत सुरक्षा खतरों, संगठित अपराध, सूचना सुरक्षा और नशीले पदार्थों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बनाए जा रहे केंद्रों को सकारात्मक कदम बताया.
- पश्चिम एशिया के संकट ने दिखाया है कि किसी एक क्षेत्र में होने वाला संघर्ष सिर्फ उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और सप्लाई चेन पर भी पड़ता है.
- एससीओ सहयोग का तीसरा स्तंभ अवसर है, जिसका मतलब है कि संगठन के सहयोग का फायदा सीधे लोगों तक पहुंचना चाहिए.
- सिर्फ आतंकियों को पकड़ना या मारना काफी नहीं है. उन्हें पैसा कौन देता है, भर्ती कैसे होती है और कहां छिपते हैं, इस पूरे नेटवर्क को खत्म करना होगा.

मोदी-पुतिन-जिनपिंग का दोस्ताना अंदाज

शिखर सम्मेलन की बैठक इसलिए खास होती है क्योंकि यहां पर चीन-रूस और भारत एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होते हैं. ये वो तिकड़ी है, जो सुपरपावर अमेरिका को भी बेचैन कर देती है. एक बार फिर से जब ये तीनों नेता आमने-सामने मिले, तो वो वायरल पल बन गया, तो ग्लोबल मीडिया में कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहेगा. हालांकि समिट के दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पहले से तय नहीं थी.

पुतिन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की याद दिलाई

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के 87 साल पूरे होने का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ऐसी वैश्विक उकसावे वाली घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जो नए युद्ध को जन्म दें. पुतिन ने कहा कि देशों को मिलकर काम करना होगा, ताकि दुनिया में नए संघर्षों को भड़कने से रोका जा सके. उन्होंने कहा कि मौजूदा सहयोग और प्रयास इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे. पुतिन ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन की शुरुआत कुछ देशों के छोटे संगठन के तौर पर हुई थी, लेकिन अब यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन गया है.

चंद्रा को झटका, दिवालिया आदेश पर लगी रोक

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 1 सितंबर. एस्सेल ग्रूप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से जुड़े दिवालियापन मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अहम निर्देश दिया. ट्रिब्यूनल ने 25 अगस्त को पारित अपने आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही चंद्रा को गारंटर के तौर पर अपनी संपत्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचने अथवा किसी अन्य के नाम ट्रांसफर करने से रोक दिया गया है.

मामले की सुनवाई के दौरान एनसीएलटी की बेंच ने पाया कि इससे पहले सुनवाई करने वाले तीन सदस्यों के आदेशों में मतभेद था. इसके बाद अब पूरे मामले को पांच सदस्यीय विशेष बेंच के समक्ष रखा गया है. इससे पहले चंद्रा के लिए करीब 6.25 करोड़ रुपये के भुगतान के जरिए व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही को निपटाने का रास्ता साफ हुआ था.

▶ संपत्तियों की बिक्री भी नहीं होगी

सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस तुरंत रद्द करें

नई दिल्ली, 1 सितंबर. नीट-यूजी पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई के बीच प्रदर्शन से संबंधित दर्ज सभी एफआईआर को रद्द करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि में हुई घटनाओं को लेकर किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज मामले, जिन्हें अदालत के समक्ष औपचारिक रूप से पेश नहीं किया गया है, उनकी भी जांच आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और उन्हें बंद माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह स्वतंत्रता दी कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस अवधि की घटनाओं के संबंध में नई एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए कह सकता है. हालांकि, दिल्ली पुलिस को 28,73 लोगों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई है.

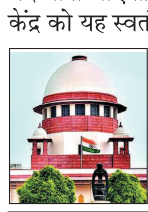

▶ केंद्र को सुको का आदेश

▶ एक नजर में ◀

योगी के खिलाफ राय ने किया मानहानि केस

लखनऊ .उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. राय ने यह केस मछली खाने को लेकर लगाए गए कथित आरोपों को लेकर लगाया है.

ट्रंप के रक्षा मंत्री ड्रिस्कॉल ने दिया इस्तीफा

वॉशिंगटन. सेना के आधुनिकीकरण और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व को लेकर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ तनाव के कारण डैनियल ड्रिस्कॉल ने अमेरिकी सेना मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया है.

78 टीआई फिर हुए सब इंस्पेक्टर

नवभारत न्यूज

भोपाल, 1 सितंबर. पुलिस मुख्यालय ने 78 पुलिस अधिकारियों की निरीक्षक पद पर हुई पदोन्नति रद्द कर दी है. ये सभी अधिकारी पहले कार्यवाहक निरीक्षक या उपनिरीक्षक के पद से निरीक्षक बनाए गए थे.

समीक्षा के दौरान सामने आया कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, कुछ पर विभागीय दंड प्रभावी है और कुछ के आपराधिक मामले अदालत में लंबित हैं. इसके बाद उनकी पदोन्नति पर दोबारा विचार किया गया और उसे निरस्त करने का फैसला लिया गया. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित पुलिस अधीक्षकों ने इन अधिकारियों के खिलाफ दंड या जांच लंबित होने की जानकारी मुख्यालय को दी थी.

- रिव्यू डीपीसी के बाद पदोन्नति हुई रद्द
- आरोपों के चलते पीएचक्यू का निर्णय, दूसरी सूची जल्द

भोपाल समेत कई जिलों के अधिकारी

पदोन्नति रद्द होने वाले अधिकारियों में भोपाल के अलावा मुरैना, मंडला, सतना, टीकमगढ़, बैतूल, छतरपुर, खंडवा, भिंड, इंदौर, रीवा, खरगोन, धार, बुरहानपुर, नीमच, उमरिया, शहडोल, ग्वालियर, मंदसौर और बालाघाट समेत कई जिलों में पदस्थ अधिकारी शामिल हैं. इनमें इंदौर नारकोटिक्स विंग, ग्वालियर पीटीएस और भोपाल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ अधिकारी भी हैं.

एसआईआर | तीसरे दौर की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा दिल्ली और महाराष्ट्र में मिले संदिग्ध मतदाता

16 राज्यों में 6.15 करोड़ वोटर लिस्ट से बाहर

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 01 सितंबर. निर्वाचन आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तीसरे चरण में प्रकाशित मसौदा मतदाता सूचियों में अब तक 6.15 करोड़ से अधिक नाम हटाए जा चुके हैं.

इस चरण में 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 36.08 करोड़ पुराने मतदाताओं के रिकॉर्ड की समीक्षा की गई. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 29.93 करोड़ नाम मसौदा सूची में बरकरार हैं, जबकि करीब 6.15 करोड़ यानी 17.04 प्रतिशत प्रविष्टियां बाहर हुई हैं.

महाराष्ट्र में 2 करोड़ नाम कटे: महाराष्ट्र में एसआईआर से पहले करीब 9.78 करोड़ मतदाता दर्ज थे. मसौदा सूची से लगभग 2.07 करोड़ नाम हटाए गए.

पहले दो चरणों में भी हटे थे करोड़ों नाम: एसआईआर के दूसरे चरण में 12 राज्यों में कुल मतदाता संख्या 5.18 करोड़ घटकर 45.81 करोड़ रह गई थी.

▶ 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया

तीसरे चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं. केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शामिल हैं. नागालैंड और त्रिपुरा के मसौदा रोल अभी प्रकाशित होना बाकी बताए गए हैं. इसलिए तीसरे चरण का मौजूदा आंकड़ा अंतिम नहीं माना जा सकता.

▶ दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रतिशत गिरावट

उपलब्ध आंकड़ों में दिल्ली में मतदाता संख्या में सबसे बड़ी प्रतिशत कमी दर्ज की गई है. पुनरीक्षण से पहले राजधानी की सूची में लगभग 1.45 करोड़ मतदाता थे. मसौदा सूची में यह संख्या घटकर करीब 97.53 लाख रह गई. इस दौरान लगभग 47.56 लाख नाम हटे.